

बजट का कार्यात्मक वर्गीकरण :-

(Functional classification of budget.)

यहाँ पर कार्य (function) का अर्थ वह 'उद्देश्य' है जिसके लिए लोक बजट से व्यय किया जा रहा है, जैसे कि खाता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। इस कारण बजट का कार्यात्मक वर्गीकरण केवल इसकी व्यय मर्यादों तक ही सीमित रहता है, क्योंकि सरकार की वित्तीय प्राप्तियों के स्रोतों को सरकार के 'कार्यों' के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वर्गीकरण के खातों पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि सरकार एवं विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के कुल व्यय का अनुमान करने के लिए तीन खातों का योग लेना चाहिए अर्थात् -

- (i) प्रशासन का राजस्व व्यय (खाता संख्या 1);
- (ii) प्रशासन और विभागीय एवं वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी व्यय (खाता संख्या 2); तथा
- (iii) वित्तीय निवेश एवं उधार और अग्रिम (खाता संख्या 4)।

इस योग में विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का राजस्व व्यय नहीं लिया जाता, क्योंकि उसे निर्दिष्ट कार्यों के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक गतिविधियों संबंधी श्रृंखला ने लोक व्यय के पाँच मुख्य वर्ग सुझाए, अर्थात्,

- (i) सामान्य सेवार्थ (general services)
- (ii) सामूहिक सेवार्थ (community services)
- (iii) सामाजिक सेवार्थ (social services)
- (iv) आर्थिक सेवार्थ (economic services)
- (v) अवर्गीय (unallocable)

परंतु भारत सरकार द्वारा बजटीय व्यय को केवल चार भागों में बाँटा गया है और सामूहिक सेवाओं को यथोचित सामाजिक अथवा आर्थिक सेवाओं में रख दिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार के व्यय के चार वर्ग हैं :

- (i) सामान्य सेवाएँ (general services)
- (ii) सामाजिक सेवाएँ (social services)
- (iii) आर्थिक सेवाएँ (economic services)
- (iv) अवर्गीय (unallocable)

1. सामान्य सेवाएँ (general services) - इस वर्ग में प्रशासन के बुनियादी ढाँचे (basic administrative machinery) पर होने वाले सभी नागरिक और रक्षा (civil and defence) व्यय शामिल हैं, जैसे कि सामान्य प्रबंधन (general administration), कर संग्रहण (tax collection), पुलिस, करोंची, सिक्का निर्माण और वकालत, वैदेशिक मामले (external affairs), रक्षा, प्राकृतिक प्रकृष्टों के लिए आयोजना - भिन्न प्रावधान आदि। परंतु विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों से जुड़े प्रशासनिक व्ययों को यथोचित अन्य कार्यात्मक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यदि कोई व्यय मूले से अधिक वर्गों के कार्यक्रमों से जुड़ी हो, तो उसे यथासंभव उनमें बाँट दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक (International Monetary Fund & World Bank) को दिए गए अंशदान (contributions) भी 'सामान्य सेवाएँ' में आते हैं। (परंतु विश्व - स्वास्थ्य - संगठन, World Health Organization, तथा खाद्य और कृषि संगठन Food and Agriculture Organization को जाने वाले राँके इस वर्ग में शामिल नहीं किए जाते।)

2. सामाजिक सेवाएँ (social services) - इस वर्ग में बुनियादी सामाजिक सुविधाएँ जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और परिवार कल्याण तथा जनस्वास्थ्य (परिवार नियोजन और विश्व



स्वास्थ्य संगठन, World Health Organization, पर विश्व स्वास्थ्य संहिता) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में श्रम कल्याण, आवास तथा अन्य सामाजिक रक्षा और कल्याण (social security and welfare) की स्कीमों भी शामिल रहती हैं।

3. आर्थिक सेवाएँ (Economic Services) - इस वर्ग में वे सारे व्यवसाय शामिल रहते हैं जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश में आर्थिक कार्यक्षमताओं का संवर्धन (promotion) होता है। इनमें कृषि और उससे जुड़ी सेवाएँ, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन (export promotion); उर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, मॉसम - विज्ञान, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, पर्यटन आदि शामिल हैं।

4. अवर्गीय (Unallocable) - इस वर्ग में व्यवसाय की वे सब मदें आती हैं जिन्हें अपर्युक्त तीन वर्गों में से किसी में भी नहीं रखा जा सकता। इन मदों में व्यवसाय की अछायागियों, पैंगाने, खाद्य उपदान (subsidies), राज्यों को सांविधिक सहायता - अनुदान (statutory grants-in-aid), विशेष उधार, विदेशों की सहायता शामिल हैं।

आर्थिक-कार्यात्मक वर्गीकरण (Economic-cum-functional Classification)

यह केंद्रीय सरकार के व्यवसाय का पंक्तियों तथा स्तंभों में एक द्विमुखी वर्गीकरण है। इसमें प्रत्येक आर्थिक वर्ग/उपवर्ग की एक पंक्ति होती है तथा प्रत्येक कार्यात्मक वर्ग/उपवर्ग का एक स्तंभ होता है। इस प्रकार एक पंक्ति के अध्ययन से किसी एक आर्थिक वर्ग/उपवर्ग पर होने वाले कुल व्यवसाय के साथ-साथ उसी व्यवसाय का विभिन्न कार्यात्मक वर्गों/उपवर्गों में बँटवारा भी उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक स्तंभ में किसी एक कार्यात्मक वर्ग/उपवर्ग पर होने वाले कुल व्यवसाय के साथ-साथ उसका विभिन्न आर्थिक वर्गों/उपवर्गों में बँटवारा भी उपलब्ध रहता है।